



### इंदौर शहर के पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण के संबंध में परियोजना

MoEFCC द्वारा Climate Change Action Programme (CCAP) के अंतर्गत स्वीकृत है जिसका क्रियान्वयन इंदौर नगर पालिक निगम के माध्यम से किया जा रहा है जिसमें 330 कुओं और बावड़ियों का जीर्णोद्धार व संरक्षण किया जायेगा। परियोजना की लागत राशि रु. 5.00 करोड़ है। लगभग 270 कुओं व बावड़ियों पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है। परियोजना हेतु केन्द्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूर्ण राशि रु. 5.00 करोड़ प्राप्त की जा चुकी है। इस परियोजना से इंदौर शहर के 16,500 परिवारों को स्वच्छ पानी की पूर्ति हो सकेगी। परियोजना मार्च 2021 तक पूर्ण की जावेगी।

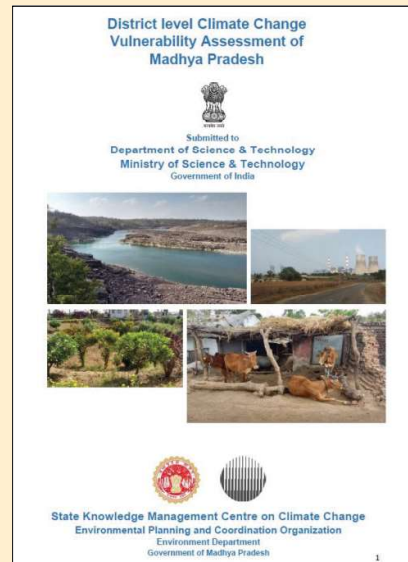


### • बुरहानपुर शहर के पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण के संबंध में परियोजना :

MoEFCC द्वारा Climate Change Action Programme (CCAP) के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। परियोजना का क्रियान्वयन बुरहानपुर नगर पालिका व वन विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। परियोजना की लागत राशि रु. 5.00 करोड़ है। पर्यावरण मंत्रालय से राशि रु. 2.50 करोड़ प्राप्त हो चुकी है जिसे क्रियान्वयन एजेंसी को हस्तांतरण भी किया जा चुका है। परियोजना के अंतर्गत बुरहानपुर शहर के 71 कुएं एवं बावड़ियों के जीर्णोद्धार व संरक्षण का कार्य किया जायेगा। साथ ही शासन के 250 शासकीय व अशासकीय भवनों में रूफ टॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य भी किया जायेगा। वर्तमान में लगभग 25 कुएं एवं बावड़ियों तथा 100 से अधिक रूफ टॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वन विभाग द्वारा भी बीट क्र. 14 व 15 में वृक्षारोपण, चेक डैम निर्माण व फेंसिंग कार्य प्रगतिशील है।



- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार से एफको को राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केंद्र (SKMCCC) के सुदृढीकरण हेतु "Strengthening of MP SKMCCC" परियोजना स्वीकृत की जा चुकी है। परियोजना में अग्रिम 5 वर्षों हेतु कुल राशि रु. 2.81 करोड़ का प्रावधान है। मार्च 2020 में परियोजना के अंतर्गत राशि रु. 55.25 लाख प्राप्त हो चुकी है। परियोजना अंतर्गत प्रशिक्षण आयोजित किये जा चुके हैं। तथा मध्यप्रदेश की जलवायु परिवर्तन संबंधित Vulnerability Assessment Report तैयार कर DST को प्रेषित की जा चुकी है।
- भारत सरकार द्वारा राज्यों को राज्य जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (MP SAPCC) को पुनः संशोधित करने हेतु के सुझाव दिए गए हैं। इस तारतम्य में संबंधित विभागों व हितधारकों के साथ परस्पर चर्चाएं कर MP SAPCC को पुनः संशोधित किये जाने हेतु कार्य किया जा रहा है। केन्द्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को संशोधित कार्य योजना का प्रारूप भेजा जा चुका है। संबंधित विभागों को संशोधित कार्ययोजना के अध्याय भेजकर उनसे अभिमत प्राप्त किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा इस कार्य हेतु राशि रु. 20.00 लाख स्वीकृत किया गए है जिससे से प्रथम किश्त के रूप में राशि रु. 12.00 लाख प्राप्त हो चुके हैं।
- एफको व World Resources Institute (WRI-India) संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के समस्त Smart Cities को "Climate Smart Cities Assessment Framework" बनाने हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इस सन्दर्भ में Inception Workshop का आयोजन दिनांक 20 फरवरी 2020 को किया गया। इसके पश्चात् WRI&India द्वारा Smart Citi में हेतु City Climate Action Plan भी बनाये जा रहे हैं। वर्तमान में ग्वालियर, इंदौर व उज्जैन के प्रारूप Action Plan तैयार किये जा चुके हैं।
- राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केंद्र (SKMCCC) एफको द्वारा विभिन्न संस्थाओं के तकनीकी सहयोग से District Climate Action Plans (DCAP) भी बनाये जा रहे हैं। इंदौर और भोपाल जिलों का Vasudha Foundation के देवास, ग्वालियर व टीकमगढ़ जिलों का IPE Global संस्था के बड़वानी, खंडवा, दमोह, मंडला, शिवपुरी व डिंडोरी जिलों का UNICEF&CANSA के तथा सिवनी व छिन्दवाड़ा जिलों का WRI-India के सहयोग से बनाये जा रहे हैं।



## 9. शोध एवं क्षमता विकास

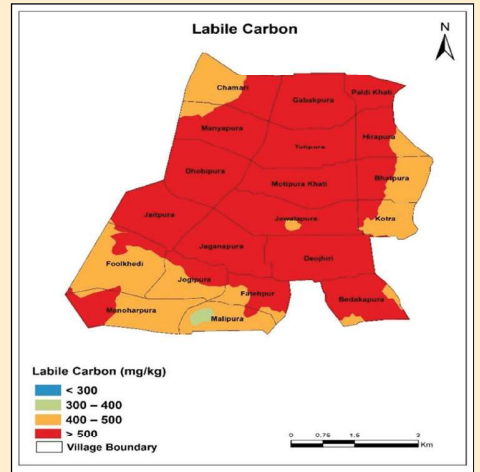
“मुख्यमंत्री जलवायु परिवर्तन PhD छात्रवृत्ति योजना” के अंतर्गत मध्यप्रदेश में स्थापित 21 चयनित राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान द्वारा नामांकित PhD के पंजीकृत अभ्यर्थियों को जलवायु परिवर्तन

पर एफको द्वारा छात्रवृत्ति प्रदाय की जा रही है। प्रति वर्ष अधिकतम 5 छात्रवृत्ति दी जा सकती है। प्रत्येक चयनित शोधार्थी को उनकी संस्था के माध्यम से 36 माह तक रू. 25,000/- प्रति माह की दर से राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त आकस्मिक व्यय हेतु राशि रू. 50,000/- प्रति वर्ष भी दी जावेगी। इसके अंतर्गत वर्ष 2016-17 में एक, वर्ष 2017-18 में पांच, वर्ष 2018-19 में तीन व वर्ष 2019-20 में दो अभ्यर्थियों को जलवायु परिवर्तन पर एफको द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। वर्ष 2020-21 में पांच अभ्यर्थियों का छात्रवृत्ति प्रदाय किये जाने हेतु चयन किया गया है।



राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केंद्र द्वारा जलवायु परिवर्तन विषय से संबंधित विषयों पर अकादमिक संस्थाओं के साथ निम्न शोध परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं जिनमें एफको द्वारा वित्तीय सहायता अकादमिक संस्थाओं को प्रदान की गई है :-

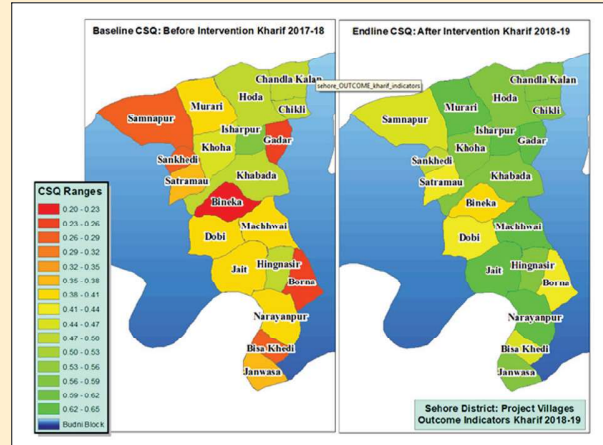
**1. मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के प्रभाव संबंधी शोध परियोजना :** भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल के साथ एक शोध परियोजना क्रियान्वित है जिसके अंतर्गत भारत शासन द्वारा एफको में स्वीकृत क्लाइमेट स्मार्ट विलेज परियोजना के 60 गावों के किसानों के खेत की मिट्टी का soil health card बनाया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 60 गावों में कृषि क्षेत्र का 1X1 किलोमीटर के ग्रिड बनाकर 360 से अधिक किसानों के खेतों से मिट्टी का सेम्पल लिया गया। इन सेम्पल से मृदा स्वास्थ्य एवं फसल उत्पादकता से संबंधित मिट्टी के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विशेषताओं के कुल 30 आवश्यक मापदंडों का परीक्षण किया गया। मिट्टी के परीक्षण परिणाम के आधार पर 60 गावों के किसानों को soil health card के साथ फसलवार अनुसंशाओं की जानकारी प्रेषित की जा रही है। इस परियोजना द्वारा यह भी ज्ञात किया जावेगा कि क्लाइमेट स्मार्ट विलेज परियोजना की मृदा एवं पोषक तत्व प्रबंधन गतिविधियों के क्रियान्वयन द्वारा किसान के खेतों में मिट्टी के उरवरता स्तर एवं इस संबंध में किसान के ज्ञान में क्या सुधार आया।



**2. "Sequestered carbon in roadside plantations: An Assessment of potential contribution in climate mitigation in Jabalpur smart city"** विषय पर राज्य वन अनुसन्धान संस्थान के साथ शोध परियोजना का निष्पादन किया गया।

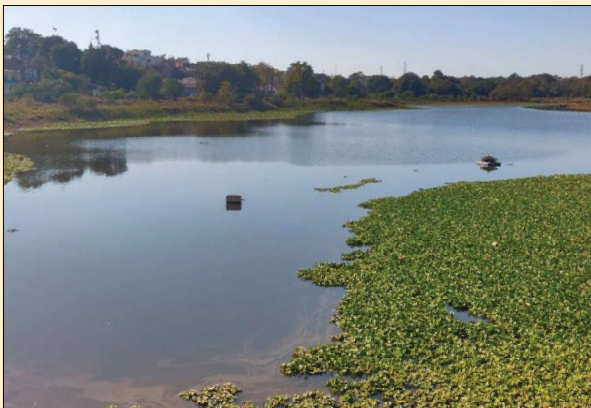
- **क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियों के प्रभाव के मूल्यांकन संबंधी शोध परियोजना :** भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल के साथ एक शोध परियोजना क्रियान्वित है। इस परियोजना के अंतर्गत क्लाइमेट स्मार्ट विलेज परियोजना की विभिन्न गतिविधियों के प्रभाव का आंकलन किया जा रहा है।
- विश्व पर्यावरण दिवस पर स्कूल ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल में राज्य जलवायु परिवर्तन एवं ज्ञान प्रबंधन केंद्र (एफको) के सहयोग से, ऑनलाइन एआईसीटीई-आरजीपीवी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीटीपी) का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 100 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

- राज्य जलवायु परिवर्तन एवं ज्ञान प्रबंधन केंद्र (एफको) और जलवायु परिवर्तन एवं सतत् विकास संस्थान ने भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंस (BSSS) के साथ संयुक्त रूप से "एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी" पाठ्यक्रम को डिजाइन किया गया एवं सम्बंधित विषय के अंतर्गत सतत् विकास लक्ष्यों, भोपाल गैस त्रासदी, EIA, ग्रीन ऑडिट आदि पर लगभग 40 छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया।
- राज्य जलवायु परिवर्तन एवं ज्ञान प्रबंधन केंद्र (एफको) ने 14 सितंबर से 26 सितंबर 2020 तक ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम "द वर्चुअल क्लाइमेट पाठशाला" आयोजित की गई। कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और सतत् विकास के मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में 22 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।



## 10. पर्यावरणीय शोध प्रयोगशाला, एफको (Environmental Research Laboratory, EPCO)

वेटलैंड संरक्षण परियोजना के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के चरण -1, मप्र के 17 जिलों के 70 वेटलैंड्स के स्वास्थ्य कार्ड को जल गुणवत्ता आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जा रहा है। इसके लिए इन जिलों के चिन्हित जल निकायों से पानी के नमूनों का संग्रह जारी है। आगर मालवा के रत्न सागर से पानी के नमूने एकत्र किए गए हैं और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश के अनुसार विभिन्न भौतिक रासायनिक मापदंडों का विश्लेषण किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में मप्र के शेष 12 जिलों से पानी के नमूने एकत्र किये जाने का कार्य संपन्न हो जायेगा। इन वेटलैंड्स के पानी की गुणवत्ता के आंकड़ों के आधार पर इन जल निकायों का हेल्थ कार्ड तैयार किया जाएगा। रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।



रत्न सागर, आगर-मालवा



गाड़त तालाब, अलीराजपुर

### सिंध सागर, ईसागढ़, जिला, अशोकनगर की जल गुणवत्ता का आकलन:

सिंध सागर, ईसागढ़, जिला, अशोकनगर की जल गुणवत्ता के मूल्यांकन भी उपचारात्मक उपायों के प्रभाव को समझने के लिए पूरा किया गया है जो इस ऐतिहासिक जल निकायों की जल गुणवत्ता में सुधार के लिए लागू किए जा रहे हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परियोजना को मंजूरी दे दी गई है और विभिन्न सुरक्षा उपायों जैसे डी सिल्टिंग, जलग्रहण प्रबंधन, वृक्षारोपण, घाटों का निर्माण किया जा रहा है।



सिंध सागर, ईसागढ़, अशोक नगर



सिंध सागर, ईसागढ़, अशोक नगर से सैम्पलिंग

### सिरपुर वेटलैंड, ईशागढ़, जिला, अशोकनगर की जल गुणवत्ता का आकलन:

सिरपुर वेटलैंड की जैव विविधता को समझने के लिए, वेटलैंड से पानी के नमूने एकत्र किए गए और विभिन्न भौतिक और जैविक मापदंडों के लिए ईआरएल, एफको में विश्लेषण किया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परियोजना को मंजूरी दी गई है और पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने और जैविक विविधता के संरक्षण के लिए विभिन्न बहाली के उपाय किए जा रहे हैं।





### प्रयोगशाला का नवीनीकरण

पर्यावरण शोध प्रयोगशाला का नवीनीकरण का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है तथा राज्य वेटलेण्ड प्राधिकरण के उद्देश्यों और गतिविधियों के साथ इसके कार्यों के साथ जोड़ा जा रहा है।

### 11. आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश 2023

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश 2023 के क्रियान्वयन के संबंध में पर्यावरण विभाग के अंतर्गत एफको की निम्नलिखित तीन गतिविधियां निर्धारित है :-

1. पर्यावरणीय मापदंडों के 100 से अधिक भू-स्थानिक आंकड़ों का उपयोग कर GIS आधारित गतिशील "ग्रीन प्लेटफॉर्म" की स्थापना।
2. जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर सहयोग, वैज्ञानिक और नीति अनुसंधान समन्वय, एवं क्षमता वर्धन हेतु सेन्टर फॉर क्लाइमेट चेंज एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट (Center for Climate Change And Sustainable Development) को सशक्त बनाने हेतु सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट (CCC-SD) तथा एफको में स्थापित स्टेट नॉलेज मैनेजमेंट सेंटर आन क्लाइमेट चेंज (SKMCCC), एफको का परस्पर विलय।
3. पर्यावरण निगरानी, हस्तक्षेप, निवेश के समन्वय एवं पर्यावरण/प्राकृतिक संसाधन क्षेत्रों में शिक्षा और जागरूकता हेतु महानिदेशक एफको की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय परिषद की स्थापना।

### 12. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेंसी कार्य (PMC)

विकास भवन हेतु एस.क्यू.सी. कार्य : निर्माणाधीन विकास भवन हेतु परियोजना पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण (एस.क्यू.सी.) का कार्य एफको द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना की लागत रुपये 70 करोड़ है। कार्य प्रगति पर है।

### 13. ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग कार्य:

नवीन वन भवन काम्पलेक्स बिल्डिंग : इस परियोजना की लागत रुपये 80 करोड़ तथा अवधि 24 माह है। इसका कार्य प्रारम्भ हो चुका है। राज्य शासन की मंशा अनुसार इस भवन को ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा के आधार पर निर्मित किया जा रहा है तथा निर्माण पश्चात केन्द्र शासन द्वारा रेटिंग हेतु अधिकृत संस्था "GRIHA" से ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्राप्त की जावेगी।

#### 14. स्ट्रक्चरल वेटिंग कार्य:

लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश की परियोजनायें : लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा निर्मित की जा रही विभिन्न निर्माण परियोजनाओं के स्ट्रक्चरल वेटिंग कार्य एफको द्वारा किये जा रहे हैं। इस हेतु प्राप्त परियोजनाओं की कुल लागत लगभग रुपये 1000 करोड़ है। कार्य सतत जारी है।

#### 15. स्ट्रक्चरल डिजाईनिंग कार्य:

संगठन द्वारा विभिन्न विभागों के निर्माणाधीन भवनों के संरचना गणना का कार्य किया गया। बेनजीर कालेज भवन द्वितीय चरण, सिक्युरिटी बैरक कम रिकार्ड रूम मंत्रालय, स्केटिंग रिक, भोपाल, कम्प्युनिटी सेंटर कम कार्मिशियल काम्पलेक्स, नरसिंहपुर कुछ प्रमुख परियोजनायें हैं।

#### 16. म.प्र. उद्यानिकी विभाग हेतु विभागीय दर अनुसूची तैयार करना:

म.प्र. उद्यानिकी विभाग हेतु विभागीय दर अनुसूची तैयार करने का कार्य विभाग द्वारा एफको को सौंपा गया है। विभागीय दर अनुसूची तैयार करने हेतु प्राथमिक जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से हितग्राहियों की कार्यशाला आयोजित कर सुझाव प्राप्त किये गये तथा प्राप्त सुझावों के अनुसार विभिन्न सामग्रियों की बाजार दर एकत्र करने तथा दरों के विश्लेषण का कार्य प्रगति पर है।

#### 17. तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना:

राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजना तैयार करने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। इसी कड़ी में मंदसौर जिले के ग्राम रूनीजा एवं धलपट की परियोजनाएं तैयार कर सौंपी जा चुकी है।

प्रदेश के 4000 से अधिक जनसंख्या वाले 273 ग्रामों के ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाना प्रस्तावित है।

#### 18. समग्र विकास योजना:

प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों हेतु समग्र विकास योजना तैयार करने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। एफको द्वारा सीहोर जिले के नसरुल्लागंज, रेहटी, बुधनी एवं शाहगंज नगरों को मॉडल टाऊन के रूप में विकसित करने हेतु प्रारम्भिक रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जा चुकी है।

इसी कड़ी में सागर, मंदसौर, विदिशा जिलों के विभिन्न नगरीय निकायों की विकास योजना तैयार करने का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

#### 19. नगरीय जल निकायों का संरक्षण एवं प्रबंधन का कार्य:

एफको द्वारा मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में स्थित तालाबों के संरक्षण और प्रबंधन की योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं। उक्त कार्यों के संचालन हेतु एफको द्वारा नगरीय निकायों के तालाबों की योजना प्रस्ताव प्राप्त कर उसकी स्वीकृति उपरांत संबंधित नगरीय निकायों को योजना क्रियान्वयन के लिए राशि उपलब्ध करायी जाती है। इस परियोजना अंतर्गत तालाब के संरक्षण के कार्य जैसे तालाब के आस पास की भूमि को विकसित करना, गाद निकालना, डिवीडिंग, जल ग्रहण क्षेत्र उपचार, घाट निर्माण, गार्डन विकसित करना, पिचिंग और फेंसिंग, जन जागरूकता एवं सौन्दर्यीकरण के कार्य किये जाते हैं। वर्ष 2020-21 में प्राप्त राशि रु. 68.48 लाख का उपयोग कर कुल 2 परियोजनाओं को वित्त पोषित किया गया है तथा 2 परियोजनायें वित्त पोषण हेतु विचाराधीन हैं।

## 20. प्रमुख रूपांकन सेवायें

### 1. वल्लभ भवन विस्तार योजना

वर्ष 2011-12 में शासन द्वारा वल्लभ भवन विस्तार परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एफ़को के माध्यम से नई दिल्ली स्थित मेसर्स सी.पी. कुकरेजा एसोसियेट्स का चयन किया गया। राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य मेसर्स शापोरजी पालोनजी कम्पनी प्रा.लि. के माध्यम से सम्पादित किया गया। योजना की संशोधित डी.पी.आर. (राशि रू. 499.74 करोड़) का अनुमोदन केबीनेट स्तर से दिसम्बर 2017 में प्राप्त किया गया और तदानुसार कार्य पूर्ण कराया गया। भवन ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर है जिसका GRIHA Rating Certification शीघ्र अपेक्षित है। नवीन निर्मित भवन का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 17.12.2018 को किया गया।

### 2. वर्तमान मंत्रालय वल्लभ भवन के उन्नयन एवं पुनः संयोजन का कार्य

वल्लभ भवन विस्तार योजना के दोनों नवीन ब्लॉक का निर्माण पूर्ण होने पर वर्तमान अथवा पुराने ब्लॉक के सुदृढीकरण/नवीनीकरण/उन्नयन योजना का निर्णय भी शासन द्वारा लिया गया। इस हेतु एफ़को के माध्यम से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित वरिष्ठ अधिकारियों की समिति द्वारा विस्तृत डिजाइन प्रस्तुतीकरण पश्चात वास्तुविदीय फर्म मेसर्स आरकॉन्स, भोपाल का चयन अक्टूबर 2018 में किया गया। सलाहकार द्वारा योजना अंतर्गत वर्तमान ब्लॉक का अवधारणा प्रस्ताव मय प्राक्कलन के स्वीकृती हेतु प्रस्तुत किया जा चुका है।

### 3. राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, भौरी-भोपाल

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा भोपाल गैस त्रासदी के प्रभावों के अध्ययन हेतु नवीन राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान की स्थापना अक्टूबर 2010 में की गई है और 20 एकड़ भूमि आवंटित की गई। एफ़को द्वारा मेसर्स ऑरकॉन्स, भोपाल के माध्यम से सेवाएँ प्रदाय की जा रही है। इसके तहत अनुसंधान कार्य हेतु बायो-सेप्टी मेन्यूल अनुसार विभिन्न प्रयोगशाला एवं संस्थान परिसर के मुख्य भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और आवसीय भवनों का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में योजना के सभी मुख्य भवनों/योजना की पुनरीक्षित लागत लगभग रू. 124 करोड़ है।

### 4. राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान भौरी-भोपाल

राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान के भोपाल सेंटर की स्थापना म.प्र. शासन के संयुक्त तत्वाधान में वर्ष 2008-09 की गई और 29 एकड़ भूमि ग्राम भौरी में आवंटित की गई है। वास्तुविदीय आकल्पन कार्य एफ़को के माध्यम से नई दिल्ली के वास्तुविद् मेसर्स सुरेश गोयल एंड एसोसिएट्स द्वारा किया जा रहा है। योजना की कुल लागत लगभग रूपये 120 करोड़ आंकलित की गई है, जिसमें से प्रथम चरण में लगभग 45 करोड़ के कार्य हैं। स्थल पर कार्य लगभग पूर्ण है और शेष बचे कार्यों हेतु प्राक्कलन (राशि रू 7.8 करोड़) फरवरी 2018 में प्रस्तुत किया जा चुका है, जिस पर अनुमोदन अपेक्षित है।

### 5. 100-कक्षीय जिला न्यायालय भवन, जबलपुर

नवीन न्यायालय भवन के लिए जबलपुर में 100-कक्षीय जिला न्यायालय भवन निर्माण के लिए वास्तुविदीय सेवाओं का कार्य एफ़को को शासन द्वारा दिया गया। एफ़को द्वारा मेसर्स सुरेश गोयल एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली को योजना के माध्यम से डिजाइन अनुमोदन पश्चात प्रस्तुत डी.पी.आर. राशि रू. 157.05 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति माह अगस्त 2013 में प्रदाय की गई। लोक निर्माण विभाग



हेतु निर्माण कार्य मेसर्स मॉन्टोंकार्लो, अहमदाबाद द्वारा किया गया। शासन द्वारा संशोधित प्रशासकीय स्वीकृती राशि रू. 191.12 करोड़ दिसम्बर 2017 में जारी की जा चुकी है। योजना के सभी मुख्य भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और माननीय मुख्य न्यायाधीश (भारत) द्वारा जून 2018 में भवन का लोकार्पण किया गया।

## 6. विकास भवन, भोपाल

वर्तमान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न परियोजनाओं के कार्यालय अलग-अलग जगहों पर स्थित हैं। सभी कार्यालयों एवं विभागध्याक्ष को एक छत के अधीन की आवश्यकता के दृष्टिगत नया भवन बनाए जाने का निर्णय लिया गया था। वर्ष 2013 में एफको द्वारा मेसर्स मेहता एसोसिएट्स इंदौर को वास्तुविद कार्य के लिए चयन करते हुए लगभग रू. 80 करोड़ है का डिजाइन/डी.पी.आर. प्रस्तुत किया गया, अपितु प्रथम चरण में रू. 53.38 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृती प्राप्त हुई है। तदानुसार स्थल पर कार्य प्रगतिरत है। द्वितीय चरण की डी.पी.आर. प्रस्तुत की जा चुकी है और प्रशासकीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

## 7. अटल बिहारी हिन्दी विश्वविद्यालय भोपाल

विभिन्न पाठ्यक्रमों की पढ़ाई हिन्दी माध्यम से करवाये जाने के उद्देश्य से अटल बिहारी हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना भोपाल में की गई। विश्वविद्यालय के स्वतंत्र परिसर हेतु राज्य शासन द्वारा ग्राम मुगालिया कोट, तहसील हुजूर, भोपाल में 50 एकड़ भूमि आवंटित करते हुए, इसके निर्माण का कार्य राजधानी परियोजना प्रशासन एवं वास्तुविदीय रूपांकन कार्य एफको को दिया गया। एफको द्वारा डिजाइन/डी.पी.आर. पर अनुमोदन उपरांत प्रथम चरण में राशि रू. 49.15 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृती सितम्बर 2015 में जारी की गई। राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य हेतु मेसर्स सुप्रीम बिल्डकॉन, भोपाल को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में प्रथम चरण योजना अनुसार सभी मुख्य भवनों का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण है और शेष कार्य बजट के अभाव में अवरूद्ध है।

## 8. रविन्द्र भवन परिसर में 1500-सीटर ऑडिटोरियम का निर्माण

मध्यप्रदेश स्थापना दिवस, दिनांक 01.11.2015 को माननीय मुख्यमंत्रीजी, श्री शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देश पर 1500-सीटर क्षमता के ऑडिटोरियम का निर्माण रविन्द्र भवन परिसर में किया जा रहा है। भोपाल में आयोजित होने वाले अनेक प्रकार के वृहद आयोजनों एवं सेमीनार/वर्कशाप/बैठकों हेतु इस ऑडिटोरियम के निर्माण की कुल अनुमानित लागत लगभग रू. 33.05 करोड़ है। इसमें अलग-अलग क्षमता के कन्वेंशन सेंटर भी लोअर ग्राउण्ड फ्लोर में प्रस्तावित हैं जिनकी अनुमानित लागत लगभग रू. 8.00 करोड़। स्थल पर प्लाजा का एवं अन्य फिनिशिंग कार्य का निर्माण पूर्णता की ओर है।

## 9. भोपाल में प्रस्तावित शौर्य स्मारक

मध्यप्रदेश शासन द्वारा उन अमर शहीदों के लिए भोपाल में शौर्य स्मारक का निर्माण किया गया है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। इस स्मारक का उद्घाटन दिनांक 14.10.2016 को माननीय प्रधान मंत्रीजी, श्री नरेन्द्र मोदीजी के कर कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ। उद्घाटन के पश्चात संस्कृति विभाग द्वारा कुछ अतिरिक्त कार्यों की आवश्यकता महसूस हुई जैसे टिकिट काउन्टर, बैगेज स्कैनर, इन्टरकॉम, HHMD, DFMD, CCTV कैमरा, कैफेटेरिया के साथ अतिरिक्त बैठक व्यवस्था एवं अतिरिक्त टॉयलेट्स, अतिरिक्त पार्किंग व्यवस्था, आदि। अतिरिक्त कार्यों की अनुमानित लागत लगभग रू. 10.00 करोड़ पर विभाग से अनुमोदन अपेक्षित है।

## 10. भोपाल में प्रस्तावित नवीन वन भवन का निर्माण

प्रदेश के महत्वपूर्ण एवं वृहद वन विभाग के विभिन्न संस्थानों के मुख्यालयीन कार्यालयों को सर्व सुविधाओं से परिपूर्ण एक भवन में स्थापित करने हेतु "नवीन वन भवन" की परिकल्पना की गई है। स्थल पर निर्माण कार्य प्रगतिरत है। वन मंत्री द्वारा 25 अगस्त 2020 की बैठक में परियोजना की लागत में हुई वृद्धि को ₹.132.00 करोड़ तक सीमित करने हेतु निर्देशित किया गया तथा स्वीकृत लागत तथा निर्माण प्रारंभ के वर्ष से आज तक लागत में हुई वृद्धि का एक तुलनात्मक प्रपत्र तैयार करने हेतु कहा गया था। उक्तानुसार एफको द्वारा कंसलटेन्ट वास्तुविद से पुनरीक्षित प्राक्कलन प्राप्त कर पुनः अनुमोदन हेतु वन विभाग को भेजा जा चुका है।

## 11. जिला विदिशा में 350-बिस्तरीय अस्पताल भवन का निर्माण

जिला विदिशा में 350-बिस्तरीय अस्पताल भवन का कार्य पूर्ण हो चुका है। दिनांक 15.11.2019 को माननीय मुख्य मंत्री, श्री कमलनाथ जी द्वारा उद्घाटन किया गया है।

## 12. बुरहानपुर में गुरु गोविंद सिंह जी के मेमोरियल म्यूजियम का निर्माण

माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास, म.प्र. शासन के निर्देश पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में म.प्र. के धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, सांस्कृतिक नगरी बुरहानपुर में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के मेमोरियल म्यूजियम का निर्माण प्रस्तावित है। कार्य की कुल अनुमानित लागत लगभग ₹. 13.98 करोड़ है। इस कार्य की निर्माण संस्था म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल बुरहानपुर है। एफको द्वारा फाइनल डी.पी.आर. अनुमोदन हेतु पुरातत्व विभाग को भेजी जा चुकी है।

## 13. संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय द्वारा संचालित 11 संग्रहालयों के उन्नयन एवं विकास का कार्य

संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय द्वारा चयनित 11 महत्वपूर्ण संग्रहालयों के डी. पी.आर., उन्नयन एवं विकास का कार्य एफको के माध्यम से बाह्य परामर्शी से चाहा गया है। सभी संग्रहालयों पर प्रथम चर्चा विभाग के साथ हो चुकी है किन्तु पुरातत्व विभाग द्वारा महाराजा छत्रसाल म्यूजियम धुबैला, जिला छतरपुर का कंजरवेशन/अपग्रेडेशन एवं विकास कार्य को प्राथमिक तौर पर कराया जा रहा है तथा इस कार्य की पुनरीक्षित डी.पी.आर. पर अनुमोदन अपेक्षित है।

## 14. विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत भोपाल स्थित विभिन्न महाविद्यालयों के अंतर्गत नवीन कार्य एवं रेनोवेशन कार्य

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत भोपाल स्थित 8 महाविद्यालयों के नवीन निर्माण तथा रेनोवेशन के कार्य एफको को सौंपे गए हैं जिनमें शासकीय गीतांजली कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शासकीय साइंस एवं कॉमर्स बेनजीर महाविद्यालय, शासकीय हमीदिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्कृष्ट महाविद्यालय संस्थान, एम.एल.बी. कन्या महाविद्यालय, मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, सरोजनी नायडू कन्या महाविद्यालय एवं नवीन महाविद्यालय (मालवीय होस्टल) सम्मिलित हैं। उक्त निर्माण कार्यों की निर्माण संस्था राजधानी परियोजना प्रशासन है। आठों महाविद्यालयों की डी.पी.आर., विश्व बैंक की गाइड लाइन अनुसार एनवायरमेंट एवं सोशल फ्रेमवर्क का विशेष ध्यान रखते हुए समय सीमा में प्रस्तुत की गई और प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त हुआ। वर्क

आर्डर पश्चात सभी महाविद्यालयों में स्थल पर कार्य प्रगतिरत है। प्रत्येक महाविद्यालय योजना की लागत लगभग रू. 6.00 करोड़ से लेकर रू.12.00 करोड़ के बीच है, और आठों महाविद्यालय की सम्मिलित लागत राशि रू. 62.86 करोड़ स्वीकृत हैं।

#### 15. ग्वालियर जिले में प्रस्तावित राजस्व भवन का कार्य

ग्वालियर जिले में राजस्व विभाग के विभिन्न कार्यालयों के लिए संयुक्त कार्यालय भवन का निर्माण कार्य ग्वालियर मुख्यालय की सीरोल पहाड़ी पर प्रस्तावित है। योजना की लागत लगभग रू. 60.83 करोड़ है। योजना अंतर्गत डी.पी.आर. पी.आई.यू., लोक निर्माण विभाग को प्रदाय की जा चुकी है तथा स्थल पर निर्माण का प्रगतिरत है।

#### 16. संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण, म.प्र. विभाग द्वारा संपादित किए जा रहे विभिन्न कार्य

##### 'अ'— मल्टीपरपज हॉल, टी.टी. नगर स्टेडियम भोपाल

उक्त योजना में मुख्य रूप से मार्शल आर्ट, कुश्ती, बार्क्सिंग एवं कराटे, ताइक्वाण्डो खेलों की गतिविधियाँ संचालित की जावेगी। योजना की लागत लगभग रू.9.47 करोड़ है। स्थल पर निर्माण कार्य प्रगतिरत है।

##### 'ब' — शूटिंग अकादमी भोपाल में होस्टल भवन

खेल एवं युवा कल्याण द्वारा संचालित विभिन्न खेल प्रशिक्षण लेने वाले खिलाड़ियों की आवासीय व्यवस्था पूर्ति हेतु विभाग द्वारा लगभग रू.10.78 करोड़ की लागत में होस्टल निर्माण का कार्य प्रस्तावित है। होस्टल भवन में 180 बिस्तर हेतु डॉरमेट्री, कोच/वार्डन हेतु निवास कक्ष, वार्डन कार्यालय, दिव्यांग खिलाड़ियों की डॉरमेट्री हेतु सुविधाओं आदि का प्रावधान किया जा रहा है।

##### 'स'— 50 मीटर शूटिंग रेंज का विस्तार कार्य

भारत सरकार द्वारा बिसन खेड़ी स्थित 50 मीटर शूटिंग रेंज का विस्तार प्रस्तावित है। योजना की लागत लगभग रू. 6.90 करोड़ है। योजना स्थल पर निर्माण कार्य प्रगतिरत है जिसका कार्य राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा करवाया जा रहा है।

#### 17. सांस्कृतिक केन्द्र / प्रशासकीय भवन कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग

जनजातीय कार्य विभाग के सांस्कृतिक केन्द्र / प्रशासनिक भवन के रूपांकन का कार्य एफ्को के माध्यम से सलाहकार वास्तुविद शैलेन्द्र शर्मा एण्ड एसोसिएट्स, भोपाल द्वारा किया जा रहा है। योजना हेतु लगभग 1.5 एकड़ की भूमि अरेरा हिल्स, भोपाल पर उपलब्ध कराई गई है। उक्त भवन की प्लानिंग ग्रीन बिल्डिंग कान्सेप्ट पर आधारित है। प्रस्तावित सांस्कृतिक केन्द्र के लिए स्पेस डिस्प्ले, आर्ट एवं क्राफ्ट गैलरी एरिया, साउण्ड सिस्टम, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए स्टेज तथा 200 लोगों के लिए सीटिंग व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। स्थल पर लगभग रू. 35.00 करोड़ की लागत में निर्माण कार्य प्रगतिरत है।

#### 18. एफ्को द्वारा वर्ष 2021 में कुछ नवीन योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जिन पर क्लाइंट विभाग से अनुमोदन एवं अनुबंध होना शेष है :-

(अ) जिला छिंदवाड़ा में आदिम जाति विकास विभाग के लिए प्रस्तावित सांस्कृतिक केन्द्र, बीजा ढाणा, तमिया।

- (ब) स्कूल शिक्षा विभाग के लिए प्रस्तावित शासकीय शाला परिसर ज्ञ.12 के छात्रों हेतु नवीन प्रोटोटाइप कम्पोजिट भवन डिजाइन, मौजूदा स्कूलों में रेट्रोफिटिंग तथा अपग्रेडेशन के वास्तुविदीय कार्य।
- (स) विधान सभा परिसर में पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ का भवन रूपांकन एवं विधान सभा परिसर की 104 एकड़ भूमि के मास्टर प्लानिंग का कार्य।

## 21. राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (State Level Environment Impact Assessment Authority - SEIAA)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र. 1533 दिनांक 14 सितंबर 2006 के तहत मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन तीन वर्ष की कार्य अवधि के लिये सतत् किया जाता है। उक्त प्राधिकरण द्वारा अधिसूचना के शेड्यूल अनुसार प्रदेश में प्रस्तावित विभिन्न परियोजनाओं को पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्रदान की जाती है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 10.10.2017 से राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का पुर्नगठन किया गया। प्राधिकरण में अध्यक्ष एवं सदस्य का चयन होता है। एफको के कार्यपालन संचालक को इस प्राधिकरण का सदस्य सचिव नामांकित किया गया है। यह प्राधिकरण राज्य स्तर पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्यरत है। इस प्राधिकरण का बजट का प्रावधान राज्य शासन द्वारा किया जाता है।

इसी तरह भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उपरोक्त अधिसूचना के तहत राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का भी गठन किया गया। इस समिति में अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के अतिरिक्त कुल 07 विषय विशेषज्ञ हैं। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को इस समिति का सचिव नामांकित किया गया है। पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं का तकनीकी परीक्षण इस समिति द्वारा किया जाता है। तदोपरांत समिति की अनुशंसायें राज्य स्तरीय पर्यावरण निर्धारण प्राधिकरण को भेजी जाती हैं। प्रकरण का अंतिम निर्णय प्राधिकरण की बैठक में लिया जाता है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण के गठन से दिनांक 31.01.2021 तक कुल 8141 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं। 01 अप्रैल 2020 से 31 जनवरी 2021 तक कुल 1122 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। इस दौरान मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय पर्यावरण प्राधिकरण की 49 बैठकें तथा मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 47 बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें 924 प्रकरणों में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई तथा शेष प्रकरण विचाराधीन है।

## 22. अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ :

### एफको पेपर, अनुपयोगी कागज पुर्नचक्रण इकाई:

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफको) द्वारा पर्यावरण परिसर में स्थित विभिन्न कार्यालयों द्वारा उत्सर्जित अनुपयोगी कागज को पुर्नचक्रित कर कार्यालयीन उपयोगी सामग्री हेतु कागज का उत्पादन किया जा रहा है। यह इकाई वर्ष 2011 से कार्यरत है।

स्थापित इकाई एक प्रदर्शन इकाई है, इसके माध्यम से उत्सर्जित अनुपयोगी कागज का पुर्नचक्रण कर अपशिष्ट प्रबंधन का एक अनूठा प्रयास है।



### उपलब्धियां:

- इकाई द्वारा स्थापना दिन से आज तक 8 मीट्रिक टन कागज को पुर्नचक्रित किया गया है।
- एफको कार्यालय की 95 प्रतिशत स्टेशनरी मांग को पूर्ण कर रहे हैं।
- अन्य शासकीय संस्थाओं की मांग आने पर उत्पादन लागत पर उत्पाद प्रदान किया जा रहा है।
- समाज को अपने अपशिष्ट प्रबंधन करने का हरित विकल्प प्रस्तुत किया जा रहा है।
- भोपाल के विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों एवं कालेज के छात्रों अपशिष्ट प्रबंधन इकाई हेतु उन्मुखीकरण करने हेतु इकाई का प्रदर्शन।
- विभिन्न संस्थाओं द्वारा ऐसी इकाई स्थापित करने हेतु प्रेरित करना।
- कार्मल कान्वेंट स्कूल, भेल भोपाल द्वारा प्रेरित होकर ऐसी इकाई स्थापित की गयी है।
- अन्य शासकीय संस्थाओं को तकनीकी मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

### एक टन पुर्नचक्रित पेपर बचाता है:

- 25 पूर्ण विकसित वृक्ष
- 30,000 लीटर पानी
- 400 किलोवाट विद्युत
- वायु प्रदूषण में कमी



### इकाई के पुर्नचक्रित हरित उत्पाद:

फाईल कवर, फाईल पैड, कान्फ्रेंस फोल्डर, प्लास्टिक विकल्प फोल्डर, लेटर हेड, लिफाफे इत्यादि।

### वेबसाइट

संस्था की वेबसाइट [www.epco.in](http://www.epco.in) में पर्यावरण संबंधी जानकारी के अतिरिक्त संस्था के कार्यकलापों की जानकारी उपलब्ध है इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया जैसे फेसबुक व टि्वटर पर भी जानकारियां उपलब्ध है। संस्था के नये पोर्टल का निर्माण किया जा रहा है जिसमें कार्यकलापो की जानकारी एवं संस्था की गतिविधियों के बारे में रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। यह समस्थ जानकारी पोर्टल [www.epco.mp.gov.in](http://www.epco.mp.gov.in) पर शीघ्र उपलब्ध की जा रही है। इसके अतिरिक्त कार्यालय की कार्यप्रणाली ई-ऑफिस पर शीघ्र ही संचालित की जा रही है।

## पुस्तकालय

संगठन में पर्यावरणीय विषयों पर एक पुस्तकालय है। जिसमें विभिन्न पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, रिपोर्ट आदि का संकलन है। पुस्तकालय का उपयोग संगठन के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ ही अन्य शोध संस्थानों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के छात्र/शोधार्थी के द्वारा किया जाता है। पुस्तकालय को अद्यतन करने के लिये नवीन तकनीकी प्रक्रिया विचाराधीन है, इससे पुस्तकालय काफी व्यवस्थित और अद्यतन हो जायेगी।

## सिंहस्थ 2028

मध्य प्रदेश शासन द्वारा सिंहस्थ 2016 परियोजना के अंतर्गत काम्प्रेहेन्सिव मेला प्लान तैयार करने का कार्य एफको को सौंपा गया था। एफको द्वारा तैयार किये गये मेला प्लान के आधार पर अधोसंरचना विकसित कर सिंहस्थ 2016 मेले का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस मेले के अभूतपूर्व सफलता को देखते हुए वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ को और अधिक सफल बनाने हेतु संगठन द्वारा सिंहस्थ 2028 का मेला प्लान तैयार करने हेतु राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा गया है।

## ग्रीन गणेश अभियान

जलीय निकायों में मूर्ति विसर्जन से होने वाले प्रदूषण को कम करने में आम नागरिकों, विशेषकर स्कूली बच्चों में जागृति पैदा करने एवं प्रदूषण नियंत्रण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एफको द्वारा पर्यावरण हितैषी गणेश प्रतिमाओं के निर्माण हेतु जागरूकता अभियान प्रारम्भ किया गया है। इस वर्ष संगठन द्वारा कोविड संक्रमण के कारण भौतिक कार्यशालाएं आयोजित नहीं की जा सकी अतः वेबिनार के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

## जल तरंग के नवीनीकरण का कार्य:

जल तरंग इन्टरप्रिटेशन सेन्टर के नवीनीकरण हेतु NID, अहमदाबाद से चर्चा कर प्रस्ताव प्राप्त किया गया है। कार्य प्रगति पर है।

## गैर पारम्परिक एवं नवकरणीय ऊर्जा स्रोत

संगठन द्वारा गैर पारम्परिक एवं नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों के दोहन के उद्देश्य से एफको कार्यालय भवन के छत पर 50 कि.वा. रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। संयंत्र की स्थापना के उपरांत कार्यालय के विद्युत ऊर्जा खपत में लगभग 42 प्रतिशत की कमी हुई है।

## लैण्डस्केपिंग/सौन्दर्यीकरण का कार्य

पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान परिसर, भोपाल के लैण्डस्केपिंग/सौन्दर्यीकरण का कार्य एफको द्वारा किया जा रहा है। इस हेतु अनुबंध निष्पादित कर आकल्पन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

## भाग – चार

### सामान्य प्रशासनिक विषय

1. नियुक्ति	–	0
2. अनुकम्पा नियुक्ति	–	0
3. समयमान वेतनमान	–	0
4. विभागीय जांच	–	1
5. न्यायालयीन प्रकरण	–	20 विचाराधीन

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत संगठन द्वारा सूचना अधिकार मैनुअल तैयार कर संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। इस मैनुअल के माध्यम से जन सामान्य को संगठन के क्रियाकलापों की जानकारी सुगमता से उपलब्ध रहती है। अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर भी आवश्यक जानकारी जन सामान्य को उपलब्ध करायी जाती है।

## भाग – पाँच

### अभिनव योजना

राज्य शासन ने जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को रेखांकित करते हुए प्रादेशिक स्तर पर कार्य करने हेतु एफको को “स्टेट डेसिगनेटेड एजेंसी” का दायित्व सौंपा है। राज्य शासन द्वारा अंगीकृत दृष्टि पत्र 2018 के मंशानुसार एफको में राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई है जिसका मूल उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से सम्बंधित ज्ञान का सृजन करना, अध्ययनों की जानकारी का संकलन करना एवं इसका सरलीकरण कर विभिन्न हितधारकों को प्रसारित करना है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलवायु ज्ञान प्रबंधन मिशन के अंतर्गत एफको को राज्य इकाई के रूप में मान्यता प्रदान की है तथा इस हेतु अनुदान स्वीकृत किया है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ग्लोब कार्यक्रम को प्रदेश में एफको द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के ईको क्लब विद्यालयों के माध्यम से एडमास्फियर, बायोस्फियर, हाइड्रोस्फियर तथा पिडोस्फियर के पर्यावरणीय संरक्षण के लिये कार्य किया जा रहा है। इसके लिए विद्यालयों को ग्लोब साइंस किंट उपलब्ध करायी गयी है। इसकी जानकारी छै। की वेबसाइट पर आम जनता के लिए उपलब्ध रहती है।

## भाग – छः

### प्रकाशन

एफको द्वारा पर्यावरण जागरूकता हेतु समय-समय पर विभिन्न ब्रोशर, पम्पलेट, मार्गदर्शिका, संसाधन सामग्री इत्यादि का प्रकाशन किया जाता है।

## भाग – सात

### राज्य महिला नीति

राज्य महिला नीति की कार्ययोजना के पालन में राज्य की महिला आयोग द्वारा की गयी अनुशंसाओं पर संगठन द्वारा अमल किया जा रहा है। संगठन में कार्यरत महिलाओं के लिए समुचित प्रसाधन व्यवस्था की गयी है। उनके बैठने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त स्थान निर्धारित है। संगठन की महिला कर्मियों के बीच समन्वय स्थापित करने व शिकायत निवारण के लिए, राज्य महिला नीति के तहत आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया गया है।

## भाग – आठ

### सारांश

राज्य की पर्यावरण नीति निर्धारण योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में एफको की भूमिका महत्वपूर्ण है। पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने में योगदान देने के लिए भारत सरकार द्वारा संगठन को **राष्ट्रीय हरित कोर योजना** हेतु प्रदेश की नोडल एजेन्सी चुना गया है। एफको द्वारा संचालित बायोस्फियर रिजर्व परियोजना से प्रदेश के जैव-विविधता क्षेत्र को पर्याप्त संरक्षण प्राप्त हो रहा है।

राज्य सरकार द्वारा एफको में **जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केन्द्र (State Knowledge Management Centre on Climate Change)** की स्थापना की गई है। इस केन्द्र को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपनी राज्य इकाई के रूप में मान्यता प्रदान कर आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। इस केन्द्र की स्थापना से प्रदेश में जलवायु परिवर्तन से संबंधित ज्ञान, जानकारी व सूचनाओं का संकलन व प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। साथ ही जलवायु परिवर्तन से संबंधित विभागों से सहयोग प्राप्त कर योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है।

**एफको इन्स्टीट्यूट ऑफ एन्वायरमेंटल स्टडीज** की स्थापना पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता विकास, ज्ञान संवर्धन एवं विभिन्न वर्गों में जन जागरूकता एवं जागृति पैदा करने के उद्देश्य से वर्ष 2011-12 में की गई थी। इसके द्वारा संचालित पीजीडीईएम कोर्स में फ्रेश ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों तथा सेवारत कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रवेश दिया जाता है। अकादमिक वर्ष 2020-21 में पीजीडीईएम कोर्स का 9वाँ बेच संचालित किया जा रहा है।

एफको द्वारा वर्ष 2011 से अनुपयोगी कागज पुर्नचक्रण इकाई के माध्यम से पर्यावरण परिसर स्थित विभिन्न कार्यालयों द्वारा उत्सर्जित अनुपयोगी कागज को पुर्नचक्रित कर उपयोगी स्टेशनरी तैयार की जा रही है। इस प्रकार अपशिष्ट प्रबंधन का उत्तम प्रदर्शन किया जा रहा है।









**पर्यावरण विभाग**